

an>

title: Need to extend benefits of 7th Pay Commission to Grameen Dak Sevak working in Post-offices.

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : माननीय अध्यक्ष महोदया, देश में लगभग 1,55,000 पोस्ट ऑफिसेज़ में लगभग 2,65,000 ग्रामीण डाक सेवक कार्यरत हैं। चाहे दिसम्बर-जनवरी की हाड़ कंपा देने वाली ठण्ड हो या मई-जून की चिलचिलाती धूप हो या जुलाई-अगस्त की बारिश हो, ये लोग अपनी मेहनत और कर्मठता के साथ कार्यशील रहते हैं। परन्तु, सदन को यह बताते हुए मुझे खेद हो रहा है कि ग्रामीण डाक सेवकों को अभी तक सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जबकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लगभग सभी विभागों में लागू कर दिया गया है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी ग्रामीण डाक सेवकों को सरकारी कार्य करने के कारण सभी तरह के लाभ देने की दिशा में निर्देश दिये हैं। ग्रामीण डाक सेवकों को ऐसा आभास हो रहा है कि सरकार उनके साथ कहीं सौतेला व्यवहार तो नहीं कर रही है।

मैं स्वयं ग्रामीण क्षेत्र से आती हूँ। इसलिए ग्रामीण डाक सेवकों की समस्याओं तथा उनकी स्थिति से परिचित हूँ। महँगाई के इस दौर में उनको मिलने वाला वर्तमान वेतन नाकाफ़ी है।

अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करती हूँ कि ग्रामीण डाक सेवकों की सेवा को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण डाक सेवकों को सातवें वेतन आयोग के लाभ दिये जाएँ ताकि बढ़ती महँगाई में वे अपने परिवार का भरण-पोषण सही रूप से कर सकें।

श्री जयप्रकाश नारायण यादव (बांका) : महोदया, मुझे श्रीमती रमा देवी जी द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाए।

माननीय अध्यक्ष : आपको इसकी अनुमति दी जाती है।

सर्वश्री भैरों प्रसाद मिश्र,

कुँवर पुणेपेद्र सिंह चन्देल,

राजेश रंजन,

नारणभाई काछड़िया,

जनार्दन सिंह सीग्रीवाल,

शरद त्रिपाठी एवं

के. अशोक कुमार को श्रीमती रमा देवी द्वारा उठाये गये विषेय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।